

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)**पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 018/2019 (GCMS 2019/00072)	दायर दिनांक 26.08.2019	निर्णय दिनांक 19.02.2021
--	---------------------------	-----------------------------

अनवान

1. उंकारलाल पिता नानालाल जाति तम्बोली उम्र 65 निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
मोबाईल 7597867731
2. नारायण लाल पिता उंकारलाल जाति तम्बोली उम्र 31 निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
3. जगदीश चन्द्र पिता उंकारलाल जी जाति तम्बोली उम्र 28 निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलान्ट्स**बनाम**

श्री तहसीलदार साहब तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

रेस्पोंडेंट

--:: प्रथम अपील विरुद्ध निर्णय श्री तहसीलदार साहब कपासन जिला चित्तौड़गढ़ मु0 नं0 009/2019 फै0ता0 23.07.2019 अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 --::

उपस्थिति :- श्री राजेन्द्र राजौरा
श्री भैरूलाल सालवी

अधिवक्ता अपीलांट
राजकीय अधिवक्ता

--:: निर्णय ::--

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत एक अपील विरुद्ध रेस्पोंडेंट के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कि अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोंडेन्ट द्वारा ग्राम हथियाना तहसील कपासन कि नवीन आराजी नंबर 1733, 1008, 1958 रकबा 0.62 हैक्टर, पर अपीलांट का अतिक्रमण होना बताकर धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत विधिवत प्रोपर नोटिस तामिल कराये बिना एक तरफा कार्यवाही कर अपीलांट को तारीख 23.07.2019 को विवादित आराजी से बेदखली एवं पेनल्टी का आदेश पारित कर दिया जिससे दुखित होकर यह अपील प्रस्तुत कि गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली एवं पेनल्टी का आदेश न्याय नियमों के विपरित होने से



निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने बेदखली, पेनल्टी का आदेश करने से पूर्व अपीलांट को जवाब एवं साक्ष्य करने का पूर्ण अवसर नहीं दिया तथा पेशी दिनांक 23.07.2019 को अपीलांट संख्या 1 उंकारलाल हाजिर हुआ जिसके तहसीलदार साहब ने उपस्थिति होना बताकर हस्ताक्षर करा दिये और कहा कि बाद में आकर अगली पेशी पर जवाब व दस्तावेज पेश कर देना किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का मौका दिये बिना तारीख 23.07.2019 को बेदखली, पेनल्टी का आदेश कर दिया जो न्याय नियमों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय से पूर्व मौके कि कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 11.07.2019 को बनाई जिस बारे में अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया न आपत्ति पेश करने का अवसर दिया और गांव के मौतबिरान के हस्ताक्षर नहीं कराकर गांव के नाबालिग लडकों के हस्ताक्षर मनमर्जी से करा लिये जिससे भी हल्का पटवारी रिपोर्ट एक तरफा होने से ऐसा आदेश निरस्त योग्य है। ग्राम हथियाना तहसील कपासन कि विवादित नवीन आराजी नंबर 1733, 1003, 1958 रकबा 0.62 हैक्टर है जिसके पुराने आराजी नंबर 553 रकबा 5 बीघा है जिस पर अपीलांट नंबर एक कि माता एवं अपीलांट नं. 2, 3 कि दादी मां श्रीमती ऐजनबाई का सन 1967, से पूर्व पुराना कब्जा होने के आधार पर राजस्थान सरकार द्वारा उक्त आराजीयात को मिसल संख्या 134/1969 के जरिये दिनांक 28.05.1971 को विधिवत कोरम आयोजित हुई तब उक्त आराजीयात आवंटन हुई है, जिस पर ऐजनबाई के नाम पर इंतकाल नंबर 231 के जरिये विधिवत इंतकाल खोला गया है जिसके बाद ऐजनबाई का बतौर खातेदार कब्जा रहा तथा ऐजनबाई कि मृत्यु के बाद विरासत से अपीलांट संख्या 1 उंकारलाल का कब्जा काश्त चला आ रहा है लेकिन दौराने सेटलमेन्ट राजस्व कर्मचारियो कि भुल से विवादित रकबा 0.62 हैक्टर को गलती से बिलानाम खातेदारी में दर्ज कर दिया जिस बारे में पता चलने पर अपीलांट द्वारा राजस्व विभाग मे इन्द्राज दुरुस्तगी बाबत कार्यवाही विचाराधीन है, लेकिन विवादित आराजी अपीलांट संख्या 1 के खाते कब्जे कि होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजात को पेश करने का मौका दिये बिना रजिंशवश गांव के अन्य लोगों के प्रभाव में आकर बेदखली एवं पेनल्टी का आदेश देकर भारी कानूनी भुल की है। विवादित आराजी को विरासत से अपीलांट संख्या 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मामला रेवेन्यू रेकार्ड मे हेरा-फेरी का है जिससे अपीलांट नं. 2, 3 का कोई संबंध नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट नं. 2, 3 को कानून के विपरित एवं मौके कि सही जांच किये बिना जो आदेश दिया गया है वह निरस्त योग्य है तथा निर्णय साईक्लोस्टाईल प्रति पर दिया गया है जो बेड-ईन-लॉ होने से भी निरस्त योग्य है। अन्य उजर वक्त बहस अर्ज करेंगे। अपील न्यायालय श्रवणाधिकार आप होकर निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश है। निर्णय दिनांक 23.07.2019 से यह अपील अन्दर अवधि पेश है। अन्त में



अपीलांट की और से प्रार्थनाकी गई कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.07.2019 को खारिज फरमाया जावे एवं अन्य उचित दाद दिलाई जावे।

इस पर अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस के तलब किया गया। रेस्पोंडेंट की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर तहसीलदार कपासन के पत्रांक/राजस्व/255 दिनांक 23/24.09.2019 से उनकी मूल पत्रावली संख्या 009/2019 निर्णय दिनांक 23.07.2019 अनवानी सरकार बनाम जगदीश, नारायण पिता उंकार वगैराह अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता है। दिनांक 19.02.2021 को राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण में सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया। इस पर उभयपक्ष अधिवक्ता की सहमति से पत्रावली में प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही ड्रॉप की जाकर मूल पत्रावली पर उभयपक्ष की सहमति से प्रकरण को सीधे बहस हेतु रखा गया।

अपीलांट्स की और से प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद अवधि प्रस्तुत की गई है। इससे अपील अपीलांट्स को गुणावगुण पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोंडेन्ट द्वारा ग्राम हथियाना तहसील कपासन कि नवीन आराजी नंबर 1733, 1008, 1958 रकबा 0.62 हैक्टर, पर अपीलांट का अतिकमण होना बताकर धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत विधिवत प्रोपर नोटिस तामिल कराये बिना एक तरफा कार्यवाही कर अपीलांट को तारीख 23.07.2019 को विवादित आराजी से बेदखली एवं पेनल्टी का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने बेदखली, पेनल्टी का आदेश करने से पूर्व अपीलांट को जवाब एवं साक्ष्य करने का पूर्ण अवसर नहीं दिया तथा पेशी दिनांक 23.07.2019 को अपीलांट संख्या 1 उंकारलाल हाजिर हुआ जिसके तहसीलदार साहब ने उपस्थिति होना बताकर हस्ताक्षर करा दिये और कहा कि बाद में आकर अगली पेशी पर जवाब व दस्तावेज पेश कर देना किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का मौका दिये बिना तारीख 23.07.2019 को बेदखली, पेनल्टी का आदेश कर दिया जो न्याय नियमों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। ग्राम हथियाना तहसील कपासन कि विवादित नवीन आराजी नंबर 1733, 1003, 1958 रकबा 0.62 हैक्टर है जिसके पुराने आराजी नंबर 553 रकबा 5 बीघा है जिस पर अपीलांट नंबर एक कि माता एवं अपीलांट नं. 2, 3 कि दादी मां श्रीमती ऐजनबाई का सन 1967, से पूर्व पुराना कब्जा होने के आधार पर राजस्थान सरकार द्वारा उक्त आराजीयात को मिसल संख्या 134/1969 के जरिये दिनांक 28.05.1971 को विधिवत कोरम आयोजित हुई तब उक्त



आराजीयात आवंटन हुई है, जिस पर ऐजनबाई के नाम पर इंतकाल नंबर 231 के जरिये विधिवत इंतकाल खोला गया है, जिसके बाद ऐजनबाई का बतौर खातेदार कब्जा रहा तथा ऐजनबाई कि मृत्यु के बाद विरासत से अपीलांट संख्या 1 उंकारलाल का कब्जा काशत चला आ रहा है लेकिन दौराने सेटलमेन्ट राजस्व कर्मचारियों कि भुल से विवादित रकबा 0.62 हैक्टर को गलती से बिलानाम खातेदारी में दर्ज कर दिया जिस बारे में पता चलने पर अपीलांट द्वारा राजस्व विभाग मे इन्द्राज दुरुस्तगी बाबत कार्यवाही विचाराधीन है। विवादित आराजी अपीलांट संख्या 1 के खाते कब्जे कि होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजात को पेश करने का मौका दिये बिना रजिंशवश गांव के अन्य लोगों के प्रभाव में आकर बेदखली एवं पेनल्टी का आदेश देकर भारी कानूनी भुल की है। इसके जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजीयात किस्म बिलानाम दर्ज अभिलिखति है एवं अपीलांट का कब्जा बिलानाम भूमि हो कर राजकीय भूमि है जिस पर अपीलांट नियमन की पात्रता नहीं रखती है, जिससे अपीलांट की अपील सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य है। प्रचलित नियमों के अनुसार बिलानाम की भूमि आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। विवादित आराजीयात राजकीय भूमि दर्ज रेकार्ड है जिस पर अतिक्रमण पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये एवं अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेखों पर दृष्टिपात कराया और बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया जाकर बाद तामील नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है, एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.07.2019 अपीलांट की उपस्थिति में विधिवत सुनाया गया है। अतः अधीनस्थ तहसीलदार, कपासन के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस समाप्त की। बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलांट नं. 2, 3 का कोई संबंध नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट नं. 2, 3 को कानून के विपरित एवं मौके कि सही जांच किये बिना जो आदेश दिया गया है वह निरस्त योग्य है तथा निर्णय साईक्लोस्टाईल प्रति पर दिया गया है जो बेड-ईन-लॉ होने से भी निरस्त योग्य है। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस पत्रावली समाप्त की। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2006(1) RRT पेज संख्या 272, 2009(2) RRT पेज संख्या 1378 पेश किये। हमने पत्रावली का बागौर अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का दृष्टिपात किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज



का अवलोकन/परिशीलन कराया। हमने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का अवलोकन किया। अधिनियम में धारा 91 के तहत व्यवस्था की गई है कि :-

91 Unauthorised occupation of Land - (1) Any person who occupies or continues to occupy any land without lawful authority shall be regarded as a trespasser and may be summarily evicted therefrom by the Tehsildar at any time of his motion or upon the application of a local authority at whose disposal such land has been placed, and any crop standing, or any building or other construction erected, or anything deposited on such land shall, if not removed within such reasonable time as the Tehsildar may from time to time fix for the purpose, be liable to be forfeited to the State and to be disposed of [in the case of any such crop, in the manner he thinks fit and in other cases] as the Collector may direct:

Provided that the Tehsildar may in lieu of ordering the forfeiture of any such building or other construction, order the demolition of the whole or any part thereof.

1[(2) Such trespasser shall further be liable to pay, for 'each agricultural year during the whole or any part whereof has been in such unauthorized occupation of the land, a penalty which may extend to fifty times the annual rent, or assessment, as the case may be, for the first act of trespass. In the case of each subsequent act of trespass, he shall by the order of Tehsildar, be liable to commitment to civil prison for a term which may extend to three months and to pay penalty to the extent as aforesaid. The amount of such penalty shall be recovered as an arrear of land revenue, and]

1[(3) Where the trespasser ordered to be committed to civil prison under subsection (2) satisfies the Tehsildar by whom he is ordered to be committed to civil prison that he intends to present an appeal, the Tehsildar shall order that such trespasser be released on his own bond for such periods will afford him sufficient time to present the appeal and obtain stay order from the Appellate Court and such order shall so long as he is so released on bond be deemed to be suspended]

(4) In any of the following cases, namely:-

(i) where the trespasser does neither vacate the land nor make appearance in response to the notice issued under sub-section (3), or

(ii) where in response to such notice, the trespasser does not vacate the land and makes appearance but-

(a) does not show any such cause, or

(b) makes any representation which is rejected after such inquiry and hearing as may be necessary in the circumstances of the case, the Tehsildar shall, unless, in the case covered by clause (ii) the trespasser undertakes to vacate the land within a week's time- and vacates it within such time order the removal of the trespasser from such land and shall remove or depute any person, to remove him therefrom and take possession thereof; and if the Tehsildar or the person so deputed is opposed or impeded in taking possession of such land, the Tehsildar shall apply to a Magistrate having jurisdiction and such Magistrate shall enforce the surrender of the land to the Tehsildar.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Tehsildar may, in case any such land belongs to the category specified in clause (ii) of the proviso to Section 97, sell it, with the approval of the Sub-Divisional Officer, to the trespasser upon payment by him of the premium therefor at the rate fixed under Section 96 and applicable to such land in addition to the assessment and penalty recoverable from him under sub-section (2) in respect of the whole period of unlawful occupation

1[(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) - (a) whoever occupies any land without lawful authority or, having occupied such land before coming into force of the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Act, 1992, fails to remove such occupation within



fifteen days from the date of service of a notice in writing calling upon him to do so by the Tehsildar shall, on conviction, be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to three years and with fine which may extend to twenty thousand rupees; and

(b) whoever, being an employee of the State Government specifically entrusted by an order of the Collector in writing with the duty to stop or prevent an offence punishable under this sub-section wilfully or knowingly neglects or deliberately omits to stop or prevent such offence, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees or with both :

Provided that, in the case of an offence under clause (a), the court may for any adequate or special reason to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than one month :

Provided also that no investigation of an offence under clause (a) of this sub section shall be made by an officer below the rank of a Deputy Superintendent of Police :

Provided further that no court shall take cognizance of an offence under clause (b) except with the previous sanction of the Collector.

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/ परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। भूमि बिलानाम दर्ज होने से पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार कपासन ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करके बेदखली, शास्ति आरोपण किया गया। विवादित आराजीयात राजकीय भूमि की श्रेणी की इस पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान में बिलानाम दर्ज रिकार्ड है जिस पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया गया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक निर्णय पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आराजीयात पर अपीलांट का किसी भी प्रकार से हक हिस्सा निहित है तो अपीलांट इस संबंध में सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में प्रश्नगत आराजीयात राजकीय भूमि दर्ज रिकार्ड है जिस पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जबकि अपीलांट द्वारा प्रश्नगत आराजीयात के संबंध में कथन किया गया है कि प्रश्नगत आराजीयात अपीलांट संख्या 1 कि माता एवं अपीलांट नं. 2, 3 कि दादी मां श्रीमती ऐजनबाई का सन् 1967, से पूर्व पुराना कब्जा होने के आधार पर राजस्थान सरकार द्वारा उक्त आराजीयात को मिसल संख्या 134/1969 के जरिये दिनांक 28.05.1971 को विधिवत कोरम आयोजित हुई तब उक्त आराजीयात आवंटन हुई है, जिस पर ऐजनबाई के नाम पर इंतकाल नंबर 231 के जरिये विधिवत इंतकाल खोला गया है, जिसके बाद ऐजनबाई का बतौर खातेदार कब्जा रहा तथा ऐजनबाई कि मृत्यु के बाद विरासत से अपीलांट संख्या 1 उंकारलाल का कब्जा काश्त चला आ रहा है लेकिन दौराने सेटलमेन्ट राजस्व कर्मचारियों कि भुल से विवादित रकबा 0.62 हैक्टर को गलती से बिलानाम खातेदारी में दर्ज कर दिया, ऐसी स्थिति में राजस्व रेकार्ड में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि को हस्तगत प्रकरण



में देखा जाना उचित नहीं है, ऐसी स्थिति में राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती के संबंध में अपीलांत सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु वर्तमान में विवादित आराजीयात बिलानाम दर्ज रेकार्ड है जिस पर अपीलांट्स द्वारा अतिक्रमण होना जाहिर होता है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को किसी भी प्रकार से सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर अपीलाधीन आदेश मनमाफिक तरीके पारित बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया जाना प्रकट होता है। हमने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कपासन से प्राप्त अभिलेख का बागौर अवलोकन, परिशीलन/परीक्षण किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.07.2019 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक त्रुटि किया जाना परिलक्षित होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार कपासन प्रकरण संख्या 009/2019 निर्णय दिनांक 23.07.2019 अनवानी सरकार बनाम जगदीश वगैराह अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार कपासन को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांत/अप्रार्थी को विधिवत नोटिस तामील करा पूर्ण सुनवाई अवसर प्रदान करते हुए अज-सरे नव निर्णय पारित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 19.02.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

